

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 19 दिसम्बर, 2024

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-99/2024.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) जो आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

2024 का विधेयक संख्यांक 38.

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 21 का संशोधन।
3. धारा 34 का संशोधन।
4. धारा 45 का संशोधन।
5. धारा 51 का संशोधन।
6. धारा 56 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 21 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 21 की उपधारा (8) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सम्बद्ध जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संदाय की तारीख को बढ़ा सकेगा किन्तु नब्बे दिन से अधिक नहीं, या पर्याप्त प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के विरुद्ध तीन से अनधिक मासिक किश्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात कर सकेगा।”।

3. **धारा 34 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (6) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु जहां किसी माल को निरुद्ध किया जाता है, वहां माल निरुद्ध करने वाले अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) को तुरन्त और किसी भी दशा में माल निरुद्ध करने के चौबीस घण्टे के भीतर, रिपोर्ट की जाएगी, जब कभी माल को चौबीस घण्टे से अधिक की किसी अवधि के लिए निरुद्ध करना अपेक्षित हो तो इसके पश्चात्कथित की अनुज्ञा मांगी जाएगी और यदि पश्चात्कथित से कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो पहला यह धारणा कर सकेगा कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।”।

4. **धारा 45 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 45 में:-

(i) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश से, अपील निम्नलिखित को होगी:-

(क) यदि आदेश किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा या चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) को;

(ख) यदि आदेश संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है, तो आयुक्त या राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को;

(ग) यदि आदेश आयुक्त या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है तो अधिकरण को।"; और

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) राज्य मुख्यालय में तैनात संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) या अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त या आयुक्त द्वारा या किसी अधिकारी, जिस पर आयुक्त की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा अपील में पारित आदेश, आगे अधिकरण को अपीलीय होगा।”।

5. धारा 51 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) आयुक्त या सम्बद्ध वृत्त का कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर और सहबद्ध कर) से नीचे की पंक्ति का न हो, धारा 50 या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाहियां संस्थित करने से या तो पूर्व या पश्चात्, ऐसे अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति से, अपराध के शमन स्वरूप कर की रकम के दो गुणा के बराबर धन राशि स्वीकार कर सकेगा, जो विक्रयों या क्रयों के आवर्त पर, जिससे कि अपराध सम्बन्धित हो, संदेय होती, जो भी अधिकतर हो।”।

6. धारा 56 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3) के खण्ड (ज) के पश्चात् परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु खण्ड (क), (च) और (छ) में उल्लिखित सूचना सम्बद्ध जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) द्वारा तभी प्रकट किए जाने के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी, जब इस निमित्त किए गए आवेदन की छानबीन के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, उसका समाधान हो जाता है कि प्रकटीकरण इस उप-धारा के अधीन अनुज्ञेय है।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य कर एवं आबकारी विभाग का पुनर्गठन सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या ई.-एक्स.-एन.-बी(1)-1/2021 तारीख 19-01-2024 और संमसंख्यांक अधिसूचना तारीख 29-01-2024 और 29-8-2024 द्वारा दो खण्डों अर्थात् आबकारी खण्ड और माल और सेवा कर खण्ड में किया गया है।

अतः विभाग के पुनर्गठन परिणामस्वरूप, अब नवगठित (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर खण्ड में पुरानी चार स्तरीय संरचना (मुख्यालय-जोन-जिला-वृत्त) के स्थान पर तीन स्तरीय संरचना (मुख्यालय-माल और सेवा कर जोन-माल और सेवा कर वृत्त है। इसके परिणामस्वरूप, (माल और सेवा कर खण्ड/सहबद्ध कर खण्ड संरचना में जिला प्रभारी का पद अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए विभाग के पुनर्गठन के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

धर्मशाला ।

तारीख:.....2024

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री ।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि) ।

धर्मशाला:

तारीख:....., 2024

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 38 OF 2024.

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)
BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 21.
3. Amendment of section 34.
4. Amendment of section 45.
5. Amendment of section 51.
6. Amendment of section 56.

Bill No. 38 OF 2024.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2024.

2. Amendment of section 21.—In the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in section 21, in sub-section 8, for the proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that the Assessing Authority may, with the prior approval of the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes) of the concerned Zone, extend the date of such payment, but not more than ninety days, or allow payment by monthly installments not exceeding three, against an adequate security or a bank guarantee.”.

3. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (6), for the proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that where any goods are detained a report shall be made immediately and in any case within twenty four hours of the detention of the goods by the officer detaining the goods to the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes) of the concerned Zone, seeking the later's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty-four hours, as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the later the former may assume that his proposal has been accepted.”.

4. Amendment of section 45.—In section 45 of the principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) An appeal from every original order passed under this Act or rules made thereunder shall lie—

- (a) if the order is made by an Assessing Authority or by an Officer-in-Charge of the check post or barrier or any other officer not below the rank of the State Taxes and Excise Officer to the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes);
- (b) if the order is made by the Joint Commissioner, State Taxes and Excise to the Commissioner or the Additional Commissioner, State Taxes and Excise, posted at the State Headquarters;
- (c) if the order is made by the Commissioner or the Additional Commissioner, State Taxes and Excise posted at State Headquarter, exercising the powers of the Commissioner, to the Tribunal.”; and

(ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) An order passed in appeal by a Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes) or by the Additional Commissioner, State Taxes and Excise posted at the State Headquarters or by the Commissioner or any officer, on whom the powers of the Commissioner are conferred, shall be further appealable to the Tribunal.”.

5. Amendment of section 51.—In section 51 of the principal Act, for sub-section(1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) The Commissioner or any other officer not below the rank of Assistant Commissioner (GST and Allied Taxes) of the concerned circle may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under section 50 or under any rule made under this Act, accept from any person accused of such offence by way of composition of offence a sum of money equal to double the amount of tax which would have been payable on the turnover of sales or purchases to which the said offence relates, whichever is greater.”.

6. Amendment of section 56.—In section 56 of the principal Act, in sub-section (3), for the proviso after clause (j), the following shall be substituted, namely:—

“Provided that the information mentioned in clauses (a), (f) and (g) may be permitted to be disclosed by the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes) of the concerned Zone only when he is satisfied, after scrutiny of the request made in this behalf and after such enquiries as he considers necessary, that the disclosure is admissible under this sub-section.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Restructuring of the State Taxes and Excise Department has been carried out by the Government vide notifications No. EXN-B(1)-1/2021 dated 19-01-2024, of even number dated 29-01-2024 and dated 29-08-2024 into two wings viz. Excise Wing and GST Wing.

Consequent upon the restructuring of the Department now, the newly formed GST/Allied Taxes Wing has three tier structure (Headquarters-GST Zone-GST Circle) instead of old four tier structure(Headquarters-Zone-District-Circle). As a result of it the post of District-in-Charge no longer exists in GST Wing/Allied Tax wing structure, hence, amendments in the Act are required in order to align with the restructuring of the Department.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

DHARAMSHALA:
THE....., 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:
THE....., 2024.
